

बैठक कार्यवृत्त

5वीं राज्य ब्रॉडबैंड समिति की बैठक – चंडीगढ़ यूटी

दिनांक: 13 मई 2025 (मंगलवार)

अध्यक्ष: श्री राजीव वर्मा, आईएस, मुख्य सचिव, चंडीगढ़ यूटी

आयोजक: श्री अनिल कुमार रंजन, अपर महानिदेशक दूरसंचार, पंजाब एल.एस.ए., दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार

राज्य ब्रॉडबैंड समिति की बैठक 13 मई, 2025 को चंडीगढ़ के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत चंडीगढ़ के उप महानिदेशक (डीडीजी) श्री बी.एम. सेतिया के स्वागत भाषण से हुई, जिसके बाद एजेंडा बिंदुओं पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई। बैठक के दौरान हुई चर्चाएँ इस प्रकार हैं:

(I) एजेंडा बिंदु 1: नए आरओडब्ल्यू नियम, 2024 के प्रभावी कार्यान्वयन पर यूटी प्रशासन के साथ निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गई:

क्रम संख्या	चर्चा बिंदु	चर्चा आयोजित	आगे की कार्यवाही
1	संघ राज्य क्षेत्र के ग्रामीण और परिधीय क्षेत्रों में ओवरहेड दूरसंचार लाइन का प्रावधान।	1. डीडीजी (चंडीगढ़) ने अध्यक्ष से अनुरोध किया कि नई दूरसंचार राइट ऑफ वे (ROW) नियमावली - 2024 के अनुसार टीएसपी (टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं) को ओवरहेड ओएफसी केबल बिछाने की अनुमति प्रदान की जाए। उन्होंने अध्यक्ष को सूचित किया कि केंद्र शासित प्रदेश के कई ग्रामीण और परिधीय क्षेत्रों में पहले से ही कुछ अन्य संस्थाओं द्वारा ओवरहेड केबल बिछाई जा चुकी है, जो टेलीकॉम ऑपरेटर नहीं हैं। 2. मुख्य वास्तुविद (Chief Architect) ने जानकारी दी कि मास्टर प्लान ग्रामीण क्षेत्रों में ओवरहेड केबल की अनुमति नहीं देता है और संभवतः ऐसी कोई भी स्थापना मास्टर प्लान के लागू होने से पहले की गई होगी। 3. इंजीनियरिंग विभाग ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में ओवरहेड केबल बिछाने के लिए कोई अनुमति जारी नहीं की जा रही है। यह जांचना आवश्यक है कि क्या अतीत में इस प्रकार की कोई अनुमति दी गई थी या नहीं।	1. अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि उन पिछली अनुमतियों की समीक्षा की जाए, तथा संबंधित ऑपरेटरों (दूरसंचार के अलावा) को उपयुक्त वैकल्पिक विकल्पों की सलाह दी जाए या सुझाव दिया जाए। 2. ऐसी कोई भी स्थापना जिसकी कानून के तहत अनुमति नहीं है, उसे लागू नहीं किया जा सकता। [कार्यवाही: एस्टेट, एमसी, शहरी नियोजन, इंजीनियरिंग विभाग] 3. अध्यक्ष ने आगे निर्देश दिया कि सभी सुविधा प्रदाताओं द्वारा एक सामान्य डक्ट के निर्माण के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव की खोज की जा सकती है और इसे यूटी प्रशासन को प्रस्तुत किया जा सकता है। [कार्यवाही: सीओआई, डीआईपीए, विभाग / सीओआई, दूरसंचार एमसी/]

		4. यह भी उल्लेख किया गया कि इन क्षेत्रों में कॉमन डक्ट की कोई व्यवस्था नहीं है।	इंजीनियरिंग विभाग]
2	RoW पोर्टल पर निजी संपत्ति फॉर्म का सक्रियण	1. शहरी नियोजन विभाग ने सभापति को सूचित किया कि केंद्र शासित प्रदेश की पिछली नीतियों, जैसे कि 2004, 2008 और 2015 में जारी की गई नीतियों के तहत, दूरसंचार टावर लगाने का प्रावधान केवल गैर-आवासीय भवनों तक ही सीमित था। 2. डीआईपीए (DIPA) के प्रतिनिधि ने अध्यक्ष को बताया कि नए आरओडब्ल्यू नियम, 2024 के तहत निजी संपत्ति पर दूरसंचार टावर लगाने का प्रावधान है और कई राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले ही इन नियमों को अपना लिया है। इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि चंडीगढ़ की 97.25% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है, जिससे बेहतर सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए दूरसंचार बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की आवश्यकता है। 3. उप महानिदेशक (चंडीगढ़) ने अध्यक्ष से अनुरोध किया कि वे वाणिज्यिक भवनों पर दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना की अनुमति देने पर विचार करें, तथा यह सुनिश्चित करें कि चंडीगढ़ की विरासत और सौंदर्य को संरक्षित रखा जाए। 4. मुख्य वास्तुकार ने बताया कि व्यावसायिक भवनों पर दूरसंचार टावर लगाने की अनुमति पहले से ही है। उन्होंने आगे बताया कि चंडीगढ़ में हर सेक्टर में कमर्शियल बिल्डिंग और मार्केट उपलब्ध हैं और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी से सुरक्षित उपयुक्त कमर्शियल बिल्डिंग पर टावर लगाए जा सकते हैं।	इस बात पर सहमति बनी कि RoW पोर्टल पर निजी संपत्ति फॉर्म (वाणिज्यिक संपत्ति पर टावर लगाने के लिए) को सक्रिय किया जाना चाहिए, बशर्ते कि इस उद्देश्य के लिए संरचनात्मक सुरक्षा सहित संपदा नियमों का अनुपालन किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निजी आवासीय भवनों पर कोई भी स्थापना स्वीकृत न हो। [कार्रवाई: संपदा विभाग/एडीसी/एनआईसी]
3	उन मामलों में वार्षिक	1. एनआईसी ने अध्यक्ष को बताया कि	अध्यक्ष ने पूछा कि यह सत्यापित

	किराये की वापसी का प्रावधान जहां सार्वजनिक विरोध या अन्य वैध न्यायोचित कारणों से टावर स्थापना का कार्य नहीं किया जाता है।	वर्तमान में किराया नगर निगम, चंडीगढ़ और संपदा कार्यालय में जमा किया जा रहा है।	किया जाना चाहिए कि क्या ये किराए एमसी/एस्टेट ऑफिस के किसी संबंधित बैंक खाते में या केंद्र शासित प्रदेश के समेकित कोष में जमा किए जा रहे हैं। यदि किराए को समेकित कोष में जमा किया जा रहा है, तो रिफंड की प्रक्रिया के लिए बजटीय प्रक्रिया की आवश्यकता हो सकती है। हालाँकि, यदि इसकी आवश्यकता नहीं है, तो एस्टेट, एमसी, एनआईसी और वित्त विभाग संयुक्त रूप से चर्चा करके तौर-तरीके प्रस्तुत करेंगे। [कार्रवाई: एमसी/एस्टेट/वित्त विभाग] अध्यक्ष ने एनआईसी को मामले की पुष्टि करने और तदनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया। [कार्रवाई: एनआईसी]
4	RoW नियमों को अपनाने के लिए आदेश जारी किया जाएगा	सचिव (आईटी) ने अध्यक्ष को अवगत कराया कि मामला अभी जांच प्रक्रिया में है।	अध्यक्ष ने एक सप्ताह के भीतर उचित जांच के साथ आदेश जारी करने को कहा। [कार्रवाई: आईटी विभाग]

(II) एजेंडा बिंदु 2: 23.12.2024 को आयोजित चौथी एससीओ बैठक के कार्यवृत्त की समीक्षा:

- 5G रोलआउट:** डीडीजी (चंडीगढ़) ने अध्यक्ष को बताया कि एयरटेल और रिलायंस जियो ने दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित 5G न्यूनतम रोलआउट लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। हालांकि, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वीआईएल) अभी भी केंद्र शासित प्रदेश में 5G सेवाएं शुरू करने की प्रक्रिया में है। अध्यक्ष ने पूछा कि क्या वीआईएल की ओर से कोई देरी/चूक हुई है और यदि ऐसा है तो दूरसंचार विभाग द्वारा कोई जुर्माना/कार्रवाई की गई है।
- ग्रे एरिया कवरेज:**
 - एयरटेल के ग्रे एरिया स्थान:**

आगे सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्र	टिप्पणी	आगे की कार्रवाई
आईएसबीटी रोड को फेज-6 मोहाली की ओर जोड़ना	एयरटेल ने निकटतम साइट पर सेक्टर एडिशन गतिविधि पूरी कर ली है और ड्राइव टेस्ट के परिणाम प्रस्तुत कर दिए हैं, जो कवरेज में उल्लेखनीय सुधार को दर्शाते हैं।	[आइटम बंद]

पंजाब विश्वविद्यालय	एयरटेल ने निकटतम साइट पर सेक्टर एडिशन गतिविधि पूरी कर ली है और ड्राइव टेस्ट के परिणाम प्रस्तुत कर दिए हैं, जो कवरेज में उल्लेखनीय सुधार को दर्शाते हैं।	अध्यक्ष ने कहा कि मामले को जल्द से जल्द और अधिमानतः 15 दिनों के भीतर समाप्त किया जाना चाहिए। [कार्रवाई: एडीसी]
पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज – सेक्टर 12	एडीसी ने अध्यक्ष को अवगत कराया कि पीईसी अधिकारियों के साथ दूसरी बैठक शीघ्र ही आयोजित होने की उम्मीद है।	
सेक्टर 15/16 आवासीय क्षेत्र एवं संपर्क सड़कें	तीव्र जन विरोध के कारण आवंटित स्थल अब उपयोग योग्य नहीं रह गया है।	अध्यक्ष ने संयुक्त दौरा करने तथा सबसे उपयुक्त समाधान की पहचान में तेजी लाने का निर्देश दिया। [कार्रवाई: एमसी चंडीगढ़/ऑपरेटर]

उप एजेंडा बिंदु	एजेंडा	चर्चा	आगे की कार्रवाई
2(बी)	बीएसएनएल के ग्रे स्थान	डीडीजी (चंडीगढ़) ने अध्यक्ष को बताया कि नेटवर्क कवरेज को मजबूत करने के लिए बीएसएनएल द्वारा नौ स्थानों का प्रस्ताव दिया गया है। हालांकि, उपकरणों की अनुपलब्धता के कारण, ये स्थान बीएसएनएल मोबाइल कवरेज के संबंध में ग्रे जोन में बने हुए हैं।	अध्यक्ष ने बीएसएनएल से पहचाने गए संदिग्ध स्थानों को कवर करने के लिए स्पष्ट समयसीमा बताने को कहा। उन्होंने इस संबंध में दूरसंचार विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई के बारे में भी पूछा। [कार्रवाई: बीएसएनएल]
2(सी)	वीआईएल के ग्रे स्थान	डीडीजी (चंडीगढ़) ने अध्यक्ष को बताया कि वीआईएल ने नेटवर्क कवरेज को मजबूत करने के लिए चार स्थानों का प्रस्ताव दिया है। इनमें से दो स्थानों-पंजाब विश्वविद्यालय (पीयू) और पीईसी-पर इंडस टावर्स द्वारा टावर लगाने के लिए विचार किया जा रहा है। शेष दो स्थानों के लिए, वीआईएल अभी भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता के माध्यम से साइट व्यवहार्यता का आकलन कर रहा है।	अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले को चालू तिमाही के भीतर जल्द से जल्द सुलझाया जाना चाहिए। [कार्रवाई द्वारा: DoT/VIL]
3	बीएसएनएल - आईपी के साथ बुनियादी ढांचे को साझा करने का मुद्दा	उप महानिदेशक (चंडीगढ़) ने अध्यक्ष को अवगत कराया कि बुनियादी ढांचा प्रदाताओं के साथ बीएसएनएल के मुद्दों का समाधान कर लिया गया है।	[आइटम बंद]
4	यूटी में QoS पैरामीटर्स प्रदर्शन विश्लेषण	1. डीडीजी (चंडीगढ़) ने अध्यक्ष को बताया कि ट्राई ने यूटी में 5 दिन का विस्तृत ड्राइव टेस्ट आयोजित किया है और एक रिपोर्ट प्रकाशित की है।	अध्यक्ष ने कहा कि ट्राई की रिपोर्ट में कार्रवाई बिंदुओं पर सभी ऑपरेटरों से फीडबैक प्राप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे निर्देश

		ऑपरेटर के अनुसार तुलना को क्यूओएस प्रदर्शन मापदंडों के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। 2. बीएसएनएल ने अध्यक्ष को बताया कि पिछले ड्राइव टेस्ट के दौरान, नियोजित साइटों में से केवल 40% ही स्थापित की गई थीं। हालाँकि, अब तक, पूरे केंद्र शासित प्रदेश में 95% साइटें स्थापित की जा चुकी हैं, जिसके परिणामस्वरूप नवंबर की स्थिति की तुलना में नेटवर्क प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।	दिया कि पंजाब विश्वविद्यालय (पीयू), पीईसी और उच्च न्यायालय को भी टाई की हॉटस्पॉट सूची में शामिल किया जाना चाहिए। [कार्रवाई द्वारा: दूरसंचार विभाग/ट्राई]
5	बीटीएस फाइबराइजेशन स्थिति	1. डीडीजी (चंडीगढ़) ने अध्यक्ष को अवगत कराया कि वर्तमान में, केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 58% बीटीएस फाइबरकृत हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 35% है। 2. उन्होंने अध्यक्ष को यह भी अवगत कराया कि माननीय संचार मंत्री (एमओसी) ने हाल ही में एनबीएम 2.0 का शुभारंभ किया है, जिसके तहत बीटीएस फाइबरीकरण लक्ष्यों को हटा दिया गया है।	[आइटम बंद]
6	हरित ऊर्जा को अपनाना खुली पहुंच	सीपीडीएल ने अध्यक्ष को अवगत कराया कि एनआईईएलआईटी वर्तमान में एक सॉफ्टवेयर विकसित कर रहा है, जिसके मई के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है।	अध्यक्ष ने सीपीडीएल को निर्देश दिया कि वह जल्द से जल्द कार्य पूरा करे और सॉफ्टवेयर विकास पूरा होने पर कार्यान्वयन की स्थिति से अवगत कराए। [कार्रवाई द्वारा: सीपीडीएल]
7	दूरसंचार चोरी के मामले	1. पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि वर्ष 2023 में कुल 9 चोरी की घटनाएं दर्ज की गईं। इनमें से तीन मामलों को आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद बंद कर दिया गया है, जबकि शेष छह मामलों की अभी भी जांच चल रही है। 2. उप महानिदेशक (चंडीगढ़) ने अध्यक्ष को बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में कुल 11 चोरी की घटनाएं (8 - डीडीआर और 3 - ऑनलाइन) दर्ज की गई थीं, और इसका विवरण चंडीगढ़ पुलिस के साथ साझा किया गया है।	अध्यक्ष ने चंडीगढ़ पुलिस को इस संबंध में सभी डीडीआर को एफआईआर में बदलने और रिपोर्ट किए गए सभी मामलों के लिए काम करने का निर्देश दिया। [कार्रवाई: चंडीगढ़ पुलिस]

8	नए RoW नियम, 2024 के प्रावधानों पर प्रशिक्षण सत्र	उप महानिदेशक (चंडीगढ़) ने अध्यक्ष को अवगत कराया कि केन्द्र शासित प्रदेश के संबंधित विभागों के लिए तीन प्रशिक्षण सत्र सफलतापूर्वक आयोजित किए गए।	[आइटम बंद]
9	रो नियम, 2024 के तहत अनुमति की वैधता और नवीनीकरण	1. उप महानिदेशक (चंडीगढ़) ने अध्यक्ष को अवगत कराया कि नगर निगम चंडीगढ़ को आरओडब्ल्यू अनुमति की वैधता/नवीनीकरण और निष्पादन समय पर विस्तृत स्पष्टीकरण प्रदान किया गया था। 2. मुख्य अभियंता (सीई), एमसीसी ने सूचित किया कि नगर निगम ने अपनी आंतरिक बैठक में, नए आरओडब्ल्यू नियम, 2024 के खंड 7 (2) (सी) को लागू करके एक निश्चित राशि की जब्ती के साथ ओएफसी बिछाने के लिए निष्पादन समय अवधि के विस्तार को मंजूरी दे दी है।	डीडीजी (चंडीगढ़) ने बताया कि दूरसंचार विभाग को हाल ही में नगर निगम से निष्पादन समयसीमा बढ़ाने के संबंध में एक पत्र प्राप्त हुआ है, और इसे मंजूरी के लिए एनबीएम को भेजा जा सकता है। [कार्रवाई: दूरसंचार विभाग]
10	CBuD ऐप	1. डीडीजी (चंडीगढ़) ने यूटी के लिए सीबीयूडी पूछताछ के तिमाही लक्ष्यों को प्राप्त करने में एडीसी के प्रयासों की सराहना की। 2. अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी निविदाओं, कार्य आदेशों और आरएफपी में सीबीयूडी अधिदेश को शामिल किया जा रहा है। 3. निदेशक (आईटी) ने अध्यक्ष को अवगत कराया कि पंजाब सरकार द्वारा जारी सीबीयूडी ऐप के संबंध में अधिदेश एक सप्ताह के भीतर जारी कर दिया जाएगा। 4. सीई, एमसी चंडीगढ़ ने अध्यक्ष को अवगत कराया कि वे अपने जल, गैस पाइपलाइन, बिजली, सड़क और अन्य बुनियादी ढांचे के लिए भी सीबीयूडी अधिदेश को शामिल कर रहे हैं।	अध्यक्ष ने सीपीडीएल को अपनी भूमिगत संपत्तियों की सुरक्षा के लिए तुरंत सीबीयूडी ऐप पर आने का निर्देश दिया। [कार्रवाई द्वारा: डीओआईटी/एडीसी/सीपीडीएल]
11	पुराने टावरों का	एसआईओ (एनआईसी) ने अध्यक्ष को	1. अध्यक्ष ने संपदा कार्यालय,

	नियमितीकरण	बताया कि कुल 1501 टावरों का सर्वेक्षण, सत्यापन और जीआईएस-मैपिंग किया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ टावरों के लिए यह स्पष्ट नहीं है कि वे टावर किस ऑपरेटर के हैं और इसकी जांच की जानी चाहिए।	एमसीसी, इंजीनियरिंग विभाग और शहरी नियोजन विभाग को जीआईएस मैप की गई सूची पर काम करने और केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में अधिकृत और अनधिकृत टावरों की कुल संख्या की पहचान करने के लिए कहा, ताकि कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सके। [कार्रवाई: सभी संबंधित विभाग] 2. अध्यक्ष ने आगे कहा कि टावरों की पूरी सूची सभी ऑपरेटरों को वितरित की जाए, ताकि अज्ञात सूची से उनके टावरों की पहचान की जा सके और यह सत्यापित किया जा सके कि उन्होंने किन टावरों के लिए अपेक्षित अनुमति प्राप्त की है। [कार्रवाई: ऑपरेटर/दूरसंचार विभाग/एनआईसी]
12	स्मार्ट मीटरिंग और कम्पोजिट बिलिंग योजना	1. सीपीडीएल ने अध्यक्ष को अवगत कराया कि उन्होंने नाइलिट से समग्र बिलिंग के लिए सॉफ्टवेयर के विकास के लिए अनुमानित लागत अनुमान और समयसीमा प्रदान करने का अनुरोध किया है। 2. सीपीडीएल ने अध्यक्ष को आगे बताया कि स्मार्ट मीटरिंग योजना के तहत, पूरे केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में स्मार्ट मीटर लगाने में लगभग दो साल लगेंगे।	1. अध्यक्ष ने इसे शीघ्रता से पूरा करने का निर्देश दिया तथा कहा कि समग्र बिलिंग सॉफ्टवेयर के विकास के लिए एक निश्चित समय-सीमा प्रस्तुत की जाए। [कार्रवाई द्वारा: सीपीडीएल] 2. अध्यक्ष ने आगे सुझाव दिया कि स्मार्ट मीटरिंग योजना के तहत औद्योगिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी जा सकती है। [कार्रवाई द्वारा: सीपीडीएल]
13	कॉमन डक्ट पर यूटी नीति	उप महानिदेशक (चंडीगढ़) ने अध्यक्ष से केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में सामान्य वाहिनी और पदों पर नीति जारी करने पर विचार करने का अनुरोध किया।	अध्यक्ष ने एमसी चंडीगढ़ से ऐसा करने तथा कॉमन डक्ट और पोस्ट पर नीति से संबंधित लागू दरों की समीक्षा करने को कहा। [कार्रवाई द्वारा: एमसी चंडीगढ़]

14	डिजिटल संचार तत्परता रैंकिंग	1. डीसीआरआर मापदंडों की समीक्षा के लिए आईडीसीसी की तिमाही समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। 2. यूटी चंडीगढ़ द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 73 डीसीआरआर मापदंडों के संबंध में डेटा प्रस्तुत करना।	अध्यक्ष ने आईटी विभाग को मई के अंत तक आवश्यक डेटा पूरा करके प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। [कार्रवाई द्वारा: आईटी विभाग]
----	------------------------------	--	---

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

सभी प्रतिभागियों की सूची

विभाग/संगठन	प्रतिभागियों का नाम	पदनाम
चंडीगढ़ यूटी	श्री राजीव वर्मा	मुख्य सचिव
	श्री मंदीप सिंह बराड़	गृह सचिव
	श्री अमित कुमार	आयुक्त (सीएमसी)
	श्री हरि कल्लिकत	सचिव (आईटी)
	सुश्री प्रेरणा पुरी	सचिव (इंजीनियरिंग विभाग)
	श्री अमनदीप सिंह भट्टी	एडीसी
	श्री नितीश सिंगला	निदेशक (आईटी)
	श्री संजय अरोड़ा	मुख्य अभियंता (एमसीसी)
	श्री सी. बी. ओझा	मुख्य अभियंता (इंजीनियरिंग विभाग)
	श्री राजीव मेहता	मुख्य वास्तुकला (डीओयूपी)
	सुश्री मनदीप	वरिष्ठ नगर नियोजक (डीओयूपी)
	सुश्री रोमा मारवाहा	मंडल नगर नियोजक (डीओयूपी)
	श्री रवि कुमार	कार्यकारी अभियंता, सीपी-1 (इंजीनियरिंग विभाग)
	श्री राकेश कुमार	एसडीओ (संपदा कार्यालय)
	श्री उदयपाल सिंह	उप पुलिस अधीक्षक (चंडीगढ़ पुलिस)
	श्री रमेश कुमार गुप्ता	एसआईओ (एनआईसी)
	सुश्री नीति	वरिष्ठ प्रोग्रामर (एनआईसी)
	श्री रवि कुमार	वरिष्ठ प्रोग्रामर (एनआईसी)
	श्री ऐश्वर्य सारस्वत	उप प्रबंधक (सीपीडीएल)
पंजाब एलएसए, डीओटी	श्री अनिल कुमार रंजन	अतिरिक्त डीजीटी
	श्री बीएम सेतिया	डीडीजी (चंडीगढ़)
	श्री राजीव शर्मा	निदेशक (अनुपालन)
	श्री पुनित कुमार	एडीजी (ग्रामीण)
	श्री सुनील भाट	एडीईटी (चंडीगढ़)
बीएसएनएल	श्री पुरूषोत्तम लाल	डीजीएम
	श्री बलविंदर कुमार	एजीएम
बीबीएनएल	श्री उपेन्द्र पाठक	डीजीएम (बीएन)
सीओआई (ऑनलाइन)	श्री दीपक गुप्ता	प्रबंधक
डीआईपीए (ऑनलाइन)	श्री ग्रीश कुमार त्यागी	महाप्रबंधक

Minutes of the Meeting

5th State Broadband Committee Meeting – Chandigarh UT

Date: 13th May 2025 (Tuesday) at 10:00 AM

Chairperson: Shri Rajeev Verma, IAS, Chief Secretary, Chandigarh UT

Convened By: Sh. Anil Kumar Ranjan, Addl DG Telecom Punjab LSA, Department of Telecommunications, Ministry of Communications, Government of India.

State Broadband Committee Meeting was held in Chandigarh on 13th May 2025 under the chairmanship of the Chief Secretary, Chandigarh. The meeting commenced with a welcome address by Shri B.M. Setia, Deputy Director General (DDG), Chandigarh followed by a detailed presentation on the agenda points. The key deliberations held during the meeting are as follows:

(I) Agenda Point 1: Following points were discussed with UT Administration on effective implementation of new RoW Rules, 2024:

Sr No	Discussion Point	Discussion Held	Further Course of Action
1	Provision of Overhead Telecommunication Line in Rural and Peripheral Areas of UT.	1. DDG (CHD) requested chair to permit Overhead OFC cable laying by TSP's as per new Telecom ROW Rules -2024. He informed the Chair that several rural and peripheral areas of the Union Territory already have overhead cables laid by entities other than telecom operators. 2. Chief Architect informed that Master Plan does not allow overhead cables in rural areas and any such installation might have been permitted before promulgation of Master Plan 3. The Engineering Department clarified, no permissions are being issued for overhead cable laying. It needs to be checked that whether some permissions were given in the past or not. 4. It was further noted that there is no provision for a common duct in these areas.	1. The Chair directed those previous permissions be reviewed, and the concerned operators (other than telecom) be advised or suggested suitable alternate options. 2. Any such installation which is not permitted under law cannot be enforced. [Action By: Estate, MC, Urban Planning, Engineering Deptt.] 3. The Chair further directed that a joint proposal may be explored for the creation of a common duct by all Facility Providers and submitted to the UT Administration. [Action By: COAI, DIPA, DoT /MC/Engg

			Deptt]
2	Activation of Private Property form on the RoW Portal	1. The Urban Planning Department informed the Chair that under previous policies of the Union Territory, such as those issued in 2004, 2008, and 2015, the provision for installing telecom towers was restricted to non-residential buildings only. 2. The representative from DIPA apprised the Chair that under the new RoW Rules, 2024, there is a provision for installing telecom towers on private property, and many States/UTs have already adopted these rules. It was further highlighted that 97.25% of Chandigarh's population resides in urban areas, necessitating enhanced telecom infrastructure to ensure better service delivery. 3. DDG (CHD) requested the Chair to consider permitting the installation of telecom infrastructure on commercial buildings, while ensuring that the heritage and aesthetics of Chandigarh are preserved. 4. Chief Architect stated that installation of telecom tower on commercial buildings is already permitted. He further stated that commercial buildings and markets are provided in every sector in Chandigarh and installation on suitable commercial buildings that are safe from structured stability can be done.	It was agreed that the private property form (for tower installation on commercial property) on the RoW Portal be activated, subject to compliance with Estate Rules including structural safety for this purpose. It must be ensured that no installation on private residential buildings gets approved. [Action By: Estate Department/ADC/NIC]
3	Provision for Refund of Annual Rent in Cases where Tower Installation is not Executed due to	1. NIC informed the Chair that currently, the rent is being deposited with the Municipal Corporation, Chandigarh and the Estate Office .	The Chair asked that it be verified whether these rents are being deposited into any respective

	Public Protests or other Valid Justified Reasons.		bank accounts of MC/Estate Office or into the Consolidated Fund of the Union Territory. If the rents are being deposited into the Consolidated Fund, the processing of refunds may require budgetary process. However, if the same is not required, then Estate, MC, NIC and Finance Department to jointly discuss and submit the modalities. [Action By:MC/Estate/Finance Deptt] The Chair further directed NIC to verify the matter and accordingly decision to be taken. [Action By: NIC]
4	Order for RoW Rules Adoption to be Issued	The Secretary (IT) apprised the Chair that the matter is currently under the vetting process.	The Chair asked to issue the order within a week's time with due vetting. [Action By: IT Deptt.]

(II) Agenda Point 2: Review of MoM of 4th SBC Meeting held on 23.12.2024:

1. **5G Rollout:** DDG (CHD) apprised the Chair that Airtel and Reliance Jio have successfully achieved the 5G minimum rollout targets set by the DoT. However, Vodafone Idea Ltd. (VIL) is still in the process of rolling out 5G services in the Union Territory. Chair asked if there is a delay/default on part of VIL and if so any penalty/action is taken by DoT.

2. Grey Area Coverage:

a. Airtel's Grey Area Locations:

Area requiring further enhancement	Remarks	Further Course of Action
Connecting ISBT Road towards Phase-6 Mohali	Airtel has completed the sector addition activity at the nearest site and has submitted the drive test results, which highlight a notable improvement in coverage.	[Item Closed]
Punjab University	ADC apprised the chair that all the meetings with PU authorities have	

	been concluded.	The Chair asked that the matter be concluded at the earliest and preferably within 15 days. [Action By: ADC]
PEC – Sector 12	ADC apprised the Chair that the second meeting with PEC authorities is expected to be held soon.	
Sector 15/16 residential area and connecting roads.	The allotted site is no longer viable due to strong public protest.	The Chair directed to conduct a joint visit and expedite the identification of the most suitable solution. [Action By: MC CHD/ Operator]

Sub Agenda Point	Agenda	Discussion	Further Course of Action
2(b)	BSNL's Grey Locations (4G)	DDG (CHD) apprised the Chair that nine locations have been proposed by BSNL to strengthen network coverage. However, due to the unavailability of equipment, these locations continue to remain in the grey zone with respect to BSNL mobile coverage.	The Chair asked BSNL to provide a clear timeline for covering the identified grey locations. He also asked about the action being taken by DoT in this regard. [Action By: BSNL]
2(c)	VIL's Grey Locations	DDG (CHD) apprised the Chair that VIL has proposed four locations to strengthen network coverage. Out of these, two locations—Panjab University (PU) and PEC—are being considered for tower installation by Indus Towers. For the remaining two locations, VIL is still assessing site feasibility through an Infrastructure Provider.	The Chair asked that the matter be addressed at the earliest within the current quarter. [Action By: DoT/VIL]
3	BSNL - Infrastructure Sharing Issue with IPs	DDG (CHD) apprised the Chair that BSNL's issues with infrastructure providers have been addressed and resolved	[Item Closed]
4	QoS Parameters Performance Analysis in UT	1. DDG (CHD) apprised the chair that TRAI has conducted a detailed 5 day drive test in UT and published a report. The operator wise comparison has been presented i.r.t. QoS performance parameters.	The Chair asked that feedback from all operators be obtained on the action points in TRAI report. He further directed that

		2. BSNL apprised the Chair that during the previous drive test, only 40% of the planned sites had been installed. However, as of now, 95% of the sites have been installed across the Union Territory, resulting in a significant improvement in network performance compared to the situation in November.	Panjab University (PU), PEC, and the High Court also be included in the Hotspot list of TRAI. [Action By: DoT/TRAI]
5	BTS Fiberization Status	1. DDG (CHD) apprised the Chair that currently, approximately 58% of BTSs in the Union Territory are fiberized, compared to the national average of 35%. 2. He further apprised the Chair that the Hon'ble Minister of Communications (MoC) recently launched NBM 2.0, under which the BTS fiberization targets have been removed.	[Item Closed]
6	Adoption of Green Energy Open Access	CPDL apprised the Chair that NIELIT is currently developing a software, which is expected to be completed by the end of May.	The Chair directed CPDL to ensure the completion at the earliest and intimate the implementation status upon completion of the software development. [Action By: CPDL]
7	Telecom Theft Cases	1. Dy.SP apprised that a total of nine theft incidents were reported in 2023. Out of these, three cases have been closed following the arrest of the accused, while the remaining six cases are still under investigation. 2. DDG (CHD) apprised the Chair that a total of 11 theft incidents were reported (8 – DDR and 3 - online) in the previous financial year, and the details of the same have been shared with Chandigarh Police.	The chair directed Chandigarh Police to convert all the DDRs in this regard into FIR and work out for all cases reported. [Action By: CHD Police]
8	Training sessions on	DDG(CHD) apprised the chair that	[Item Closed]

	provisions of new RoW rules, 2024	three training sessions were successfully conducted for concerned departments of UT.	
9	Validity and Renewal of Permission under Row Rules, 2024	1. DDG (CHD) apprised the chair that the detailed clarification was provided on the validity/ renewal and execution time of RoW permission to MC CHD. 2. The Chief Engineer (CE), MCC informed that the Municipal Corporation, in its in-house meeting, has approved the extension of the execution time period for OFC laying by invoking Clause 7(2)(c) of the new RoW Rules, 2024, with the forfeiture of a certain amount.	DDG (CHD) informed that the DoT has recently received a letter from the Municipal Corporation regarding the extension of the execution timeline, and the same may be forwarded to NBM for approval. [Action By: DoT]
10	CBuD App	1. DDG (CHD) appreciated ADC's efforts in achieving the quarterly targets of CBuD enquiries for UT. 2. CBuD mandate is being incorporated across all tenders, work orders, and RFPs to ensure compliance. 3. The Director (IT) apprised the Chair that the mandate regarding the CBuD App, as issued by the Punjab Government, will be released within a week. 4. CE, MC CHD apprised the Chair that they are incorporating the CBuD mandate for their Water, Gas Pipeline, Electricity, Road, and other infrastructure as well.	The Chair directed CPDL to onboard onto the CBuD App immediately in order to safeguard their underground assets. [Action By: DoIT/ADC/CPDL]
11	Regularization of Old Towers	SIO (NIC) apprised the chair that a total of 1501 towers have been surveyed, verified and GIS-mapped. He stated that for some of the towers it is not clear as to which operator those tower belongs and the same needs to be checked.	1. The Chair asked the Estate Office, MCC, Engineering Department, and Urban Planning Department to work on the GIS mapped list and identify the total number of authorized and unauthorized

			towers in the Union Territory (UT) for actions in accordance with law. [Action By: All concerned Departments] 2. The Chair further asked that the complete list of towers be circulated to all operators, to identify their towers from the unidentified list and to verify for which towers they have obtained requisite permission for. [Action By: Operators/DoT/NIC]
12	Smart Metering and Composite Billing Scheme	1. CPDL apprised the Chair that they have requested NIELIT to provide an approximate cost estimate and timeline for the development of software for composite billing. 2. CPDL further informed the Chair that under the smart metering scheme, it will take approximately two years to complete the installation of smart meters across the Union Territory (UT).	1. The Chair directed the same to be expedited and asked that a firm timeline be presented for the development of the composite billing software. [Action By: CPDL] 2. The Chair further suggested that the industrial sector may be prioritized under the smart metering scheme. [Action By: CPDL]
13	UT Policy on Common Duct	DDG (CHD) requested the Chair to consider issuing a policy on the common duct and posts in the Union Territory (UT).	The Chair asked MC Chandigarh for the same and to examine for review of applicable rates related

			to the policy on common duct and posts. [Action By: MC CHD]
14	Digital Communication Readiness Ranking	1. Quarterly review meeting of IDCC to be held to review DCRR parameters. 2. Submission of data by UT CHD i.r.t. 73 DCRR parameters for the FY 2024-25.	The Chair directed the IT Department to complete and submit the required data by the end of May. [Action By: IT Deptt.]

The Meeting ended with a vote of thanks to the Chair.

Note: Hindi version follows.

List of All Participants

Dept/Org	Name of Participants	Designation
Chandigarh UT	Sh. Rajeev Verma	Chief Secretary
	Sh. Mandip Singh Brar	Home Secretary
	Sh. Amit Kumar	Commissioner (CMC)
	Sh. Hari Kallikat	Secretary (IT)
	Ms. Prerna Puri	Secretary (Engineering Dept.)
	Sh. Amandeep Singh Bhatti	ADC
	Sh. Nitish Singla	Director (IT)
	Sh. Sanjay Arora	Chief Engineer (MCC)
	Sh. C. B. Ojha	Chief Engineer (Engineering Deptt.)
	Sh. Rajiv Mehta	Chief Architecture (DoUP)
	Ms. Mandip	Senior Town Planner (DoUP)
	Ms. Roma Marwaha	Divisional Town Planner (DoUP)
	Sh. Ravi Kumar	Executive Engineer, CP-I(Engineering Dept.)
	Sh. Rakesh Kumar	SDO (Estate Office)
	Sh. Udaypal Singh	Dy.S.P (CHD Police)
	Sh. Ramesh Kumar Gupta	SIO (NIC)
	Ms. Neeti	Sr. Programmer (NIC)
	Sh. Ravi Kumar	Sr. Programmer (NIC)
	Sh. Aishwary Saraswat	Dy. Manager (CPDL)
Punjab LSA, DoT	Sh. Anil Kumar Ranjan	Addl. DGT
	Sh. BM Setia	DDG (CHD)
	Sh. Rajeev Sharma	Director (Compliance)
	Sh. Punit Kumar	ADG (Rural)
	Sh. Sunil Bhat	ADET (CHD)
BSNL	Sh. Purushotam Lal	DGM
	Sh. Balvinder Kumar	AGM
BBNL	Sh. Upender Pathak	DGM (BN)
COAI(Online)	Sh. Deepak Gupta	Manager
DIPA(Online)	Sh. Greesh Kumar Tyagi	General Manager